उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह): प्रदेश सरकारों के कर्मचारी, महापालिकाओं के कर्मचारी और म्युनिसिपल बोर्ड आदि के कर्मचारियों के मिसलेनियस, ब्यूरोज, म्युनिसिपैलिटीज, आदि के साथ सैंट्रल गवर्नमेंट का कोई वास्ता नहीं है। कानूनन हमें कोई अधिकार नहीं उनकी सैलेरी और एलाउंसेज के मुतल्लिक कुछ बात तय करने का लिहाजा यह सवाल नहीं उठता है।

खाद्य तेल का आयात

*172. श्री भारत सिंह चौहान :

श्री माधवेन्द्र दत्त :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य तेल की कमी को ध्यान में रखते हुए, विदेशों से इसका आयात करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तेल का कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान आयात की जाने वाली वास्तविक मात्रा कई एक कारणों पर निर्भर करेगी, जैसे कि देश के भीतर वास्तविक उत्पादन, वनस्पति उद्योग आदि के लिये अपेक्षित खाद्य तेलों के मूल्यों के बारे में सापेक्ष स्थिति। विनिर्माताओं के हितों तथा कमी को पूरा करने की उनकी पहल को संरक्षण देने की दृष्टि से खाद्य तेलों का आयात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है।

श्री भारत सिंह चौहान : खाद्य तेलों की वास्तविक मांग कितनी है और कितना आप इम्पोर्ट कर रहे हैं ताकि आवश्यक वास्तविक जो मांग देश के अन्दर है उसकी पूर्ति हो सके ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : चालू वर्ष के अन्दर खाद्य तेलों की मांग 35.65 लाख टन है जिस के अगेंस्ट प्रोडक्शन 24 और 26 लाख टन के बीच में है। जो बीच का गैप है इसको जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि भारत सरकार ने तेल का आयात करके, जो ओ जी एल को खत्म करके केवल एस टी सी के माध्यम से, पूरा करने का फैसला किया है। इस में जो हमारे वनस्पति के कारखाने हैं उनकी मांग भी शामिल है, राज्य सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मांग आती है वह भी शामिल है और इसके साथ साथ जो देश की रिफाइनरीज हैं उनकी भी जो तेल की मांग होती है शामिल है और सब प्रकार की मांगों को शामिल करके यह प्लान बनाया गया है।

श्री भरत सिंह चौहान : जो इम्पोर्ट आप तेल कर रहे हैं और जो यहां के स्थानीय उत्पादक हैं उनको जो मूल्य मिलता है उन दोनों में कितना अन्तर है और इम्पोर्ट प्राइस जो आप फिक्स करते हैं क्या उसका भी दुष्प्रभाव यहां के उत्पादकों पर पड़ता है, इसका भी आपने एसेसमेंट किया है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो देश में खाद्य तेलों का उत्पादन करते हैं उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसको ध्यान में रख कर ही खाद्य तेलों का आयात एस टी सी के द्वारा रेग्युलेट किया गया है और पहले जो ओ जी एल में आयात की छूट थी उसको समाप्त किया है। उत्पादकों के हितों पर कुठाराघात न हो इसलिए इस को अपनाया गया है।

श्री चतुर्भुज : बड़े, बड़े सेठों, कम्पनियों और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए आपने चाय, बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड की स्थापना कर रखी है लेकिन जो खाद्य तेल किसान उत्पादन करते हैं उनके लिए भी कोई बोर्ड बनाने का आप विचार कर रखते हैं ताकि इस में जो छोटे किसान लगे हुए हैं उनको पूरा भाव मिल सके और उनके हितों की रक्षा हो सके ? क्या आप इस तरह का कोई बोर्ड बनाएंगे जो मूंगफली, सोयाबीन आदि का उत्पादन करने वालों के हितों का ध्यान रख सकें ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जहां तक किसान के हितों का सवाल है भारत सरकार इस सम्बन्ध में पूरी जागरूक है और हर सम्भव प्रयास किये गये हैं कि किसान के हितों को किसी प्रकार का कुठाराघात न हो।

बोर्ड का जहां तक सवाल है अभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है. और ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपने आप इस दृष्टि से किसानों के हितों को देख रही है। मैं बताना चाहूंगा कि यह पहला अवसर है कि जो तिलहन हैं उनको जो समर्थन मूल्य दिया गया है, वह केवल दिया ही नहीं गया है, बल्कि जो पहले नहीं थे उनको पहले घोषित किया गया है और जो पहले से घोषित थे उनके समर्थन मूल्यों को लगातार बढ़ाया गया है। जैसे मस्टर्ड सीड का समर्थन मूल्य 1977–78 में 225 रु० था वह 1978–79 में 245 रु० किया गया है, ग्राउण्ड नट का 76–77 में 140 रु० था वह 1978–79 में 175 रु० किया गया है, सोयाबीन का 1976–77 में 145 रु० था उसको 1978–79 में 175 रु० किया गया है। इसी प्रकार से सनफ्लावर का 1976–77 में 150 रु० समर्थन मूल्य था उसको बढ़ा कर 1978–79 में 175 रु० किया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है।

THE MINISTER OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): There is a proposal under the consideration of the Government to have one Corporation for edible oils and oil seeds. The matter is under the consideration of the Government.

SHRI YADVENDRA DUTT: Our previous experience has been that all the edible oil imported has not arrived in time. The main demand for edible oil comes in the marriage season. May I know what steps the Government is taking to see that these edible oils which are being imported are brought here before the marriage season starts so that unnecessary profiteering does not take place in the country?

SHRI MOHAN DHARIA: Government is well aware of the marriage season and also various festivals in the country. Therefore, it is quite in advance of the starting of the year that the oil plan is prepared for the country. An assessment of the crop is made and an assessment is also made as to what would be the production in the country, what would be the requirements of the country and what is the gap. On that basis, in a planned manner, we are having our imports. That is why you see that the prices of oils in the country have remained stabilised.

Import of Raw Opium by Multinationals of U.S. and U.K. from India

*178. DR. BIJOY MONDAL:

SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two multinationals of U.S. and U.K. and few other agencies are importing nearly 25 tonnes of raw opium and its derivatives like morphine and heroin from India in excess of their actual consumption for circulation and sale in clandestine drug market;

(b) whether it is also a fact that the price of this opium in India is Rupees one thousand per kg. and it fetches nearly Rupees 55 thousand in the U.S. drug market;

(c) whether Government propose to check this malpractice and also to smash this racket; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) No, Sir. India exports opium to three farms each in U.S.A. and U.K. for medicinal purposes only and on the basis of import authorisations issued by the respective Government of these countries. The total quantity of opium exported to these two countries in the year 1978 was 457 tonnes. No morphine or heroin was exported from India. Under the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, the concerned countries are required to limit their imports of opium as well other narcotic drugs to their estimated requirements as approved by the International Narcotics Control Board and also keep strict controls to ensure that these drugs are actually utilised for medicinal purpose only, and are not diverted to illicit channels.

(b) Our present export price of opium is US $ 6 per unit of anhydrous morphine per kg. of opium (*viz.*, about US $ 60 per kg. of opium). We are however not aware of price of opium in the illicit drug market in the U.S.A.

(c) and (d). In view of replies to (a) and (b). above, no action is called for on our part.

DR. BIJOY MONDAL: We find that in this country and in the international market, illegal transaction in opium is going on on a considerable scale. May I know from the Minister whether there is some illegal involvement of these firms in this illegal dealing?